

# यूपी में निवेश के नए द्वार खोलेगा इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो

जासं, लखनऊ : प्रदेश में आर्थिक विकास को गति देने व विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो (यूपीआईटीईएक्स) 2024 का आयोजन होगा। पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) इसकी मेजबानी कर रहा है। पांच दिनी आयोजन 25 से 29 जनवरी तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। देश-विदेश की प्रदर्शनी के साथ टैलेंट शो और सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे।

मंगलवार को विभूतिखंड में पीएचडीसीसीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डा. रंजीत मेहता ने पत्रकारों से कहा कि एक्सपो में



ट्रेड एक्सपो की जानकारी देते क्षेत्रीय निदेशक अतुल श्रीवास्तव व अन्य • पीएचडी चैंबर

दुनियाभर से 300 से अधिक कंपनियां आ रही हैं। ये मंच न केवल यूपी की क्षमता को उजागर करता है, बल्कि आर्थिक विस्तार के लिए अहम अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को भी बढ़ावा देगा। इसमें अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने का बढ़िया

अवसर होगा। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में विकास के नए रास्ते तलाशने वाले बिजनेस इसका लाभ उठा सकते हैं।

शुभम गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुदीप गोयनका ने कहा कि आयोजन राज्य की वन

ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लक्ष्य में योगदान देने में अहम भूमिका निभाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। आयोजन में कृषि-खाद्य और फार्म, वास्तुकला और भवन, जीवन शैली और उपभोक्ता एक्सपो, फैशन स्ट्रीट और फर्नीचर, सौर ऊर्जा और आटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों का प्रदर्शन होगा। क्षेत्रीय निदेशक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में दूसरी बार ऐसा एक्सपो कर रहे हैं। यहां पीएचडीसीसीआई के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल डा. जतिंदर सिंह, सह अध्यक्ष राजेश निगम आदि मौजूद रहे।

## ये कंपनियां आएंगी

ट्रेड एक्सपो में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की कंपनियां होंगी। इसमें जम्मू-कश्मीर, झारखंड व छत्तीसगढ़ जैसे भारतीय क्षेत्रों के साथ-साथ तुर्की, थाइलैंड, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान जैसे देश सक्रिय रूप से भाग लेंगे, जिनका लक्ष्य राज्य के व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना है। एमएसएमई मंत्रालय, केंद्र सरकार, डिपार्टमेंट आफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उग्र ओडीओपी, इंवेस्ट यूपी, खादी और ग्राम उद्योग, जेकेटीपीओ, नाबार्ड, सिडबी और एसबीआई जैसी उल्लेखनीय सरकारी संस्थाएं शामिल होने वाली हैं।